एम. विश्वेश्वरा शास्त्री

बनाम

एम. गोपालकृष्णा भाट और अन्य

7 मार्च, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पंता, जे. जे.]

दलीलें-लिखित वक्तव्य-निर्दिष्ट समय के भीतर दाखिल करने के लिए निर्देश दाखिल करने में देरी-पक्ष की प्रामाणिक गलती के कारण-दायर करने के लिए समय बढ़ाने के लिए किए गए गलती आवेदन का एहसास होने पर-आवेदन को अस्वीकार करना-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःपार्टी दाखिल करने के लिए विस्तारित समय की हकदार थी क्योंकि उनकी सदभावना साबित हुई-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश VIII.

सिविल न्यायाधीश ने एक पक्षीय निर्णित मुकदमे की बहाली के लिए याचिका को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ पहली अपील की अनुमति कोस्ट के भुगतान पर दी गई थी, जिसमें अपीलार्थी को 2 सप्ताह के भीतर लिखित विवरण दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। अपीलार्थी के अनुसार उन्हें उनके वकील द्वारा सूचित किया गया था कि लिखित वक्तव्य 2 महीने के भीतर दाखिल किया जाना है। तदनुसार उन्होंने 2 महीने के भीतर लिखित विवरण दाखिल किया और कोस्ट की पेशकश भी

की। दूसरे पक्ष के वकील ने भुगतान में देरी के आधार पर कोस्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया। प्रमाणित प्रतियों को देखने पर, अपीलार्थी ने देखा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया समय 2 सप्ताह का था न कि 2 महीने का, इसलिए उन्होंने समय बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया।उसी को संक्षेप में खारिज कर दिया गया था। अतः यह वर्तमान अपील प्रस्तुत हुई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

अपीलार्थी ने पर्याप्त कारणों का आधार दिया था कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहा था। ईमानदारी को विस्तार से बताया गया है और वास्तव में, वादी द्वारा किए गए बयानों से इनकार करने वाला कोई जवाब नहीं था जो विरोधी पक्ष नहीं था। ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय ने आवेदन को संक्षेप में अस्वीकार करना उचित नहीं माना।[पैरा 9 और 10]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2000 की सिविल अपील सं. 5809

(आई. ए. सं. एम. एफ. ए. सं. 2/1999 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतिम विवादित आदेश दिनांक 24.11.1999 से।)

अपीलार्थी के लिए एस. एन. भट।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

डॉ. अरिजीत पासायत, जे.

1. अपीलार्थी कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की वैधता पर सवाल उठाता है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दिनांकित पूर्व आदेश का पालन करने के लिए समय बढ़ाने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. तथ्यात्मक पहलुओं का एक संक्षिप्त संदर्भ पर्याप्त होगाः

3. अपीलार्थी ने विविध याचिका दायर की।सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'संहिता') के आदेश XLIII नियम 1 (r) के तहत पहली अपील, विद्वत सिविल न्यायाधीश पुत्तूर (डी. के.) द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, जिसमें मुकदमे की बहाली के लिए संहिता के आदेश XVII नियम 2 के साथ पठित आदेश IX नियम 13 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसे एकतरफा घोषित किया गया था। अपीलार्थी मुक़दमे में प्रतिवादी संख्या 5 था।

4. दिनांक 25.6.1999 के आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देशों के साथ अपील की अनुमति दीः

> "परिणामस्वरूप, 1,000/- रुपये की लागत के भुगतान पर अपील की अनुमति दी जाती है। विवादित आदेश को अलग कर दिया जाता है। अपीलार्थी को इस आदेश की

तारीख से 2 सप्ताह के भीतर लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है और निचली अदालत आवश्यक विवाद्यक तैयार करने के बाद इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करेगी।"

5. यह अपीलार्थी का मामला है कि उसके वकील ने 30.6.1999 पर उसे गलत सूचना दी कि लिखित बयान दो महीने के भीतर दायर किया जाना था और उक्त समय के भीतर लागत का भुगतान किया जाना था। लिखित बयान 2.8.1999 पर दिया गया था और वादी के विद्वान वकील को लागत की पेशकश की गई थी। उक्त विद्वान वकील ने इस आधार पर राशि स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यह राशि नियत तिथि के बाद दी गई थी। अपीलार्थी ने जमा स्वीकार करने के लिए सिविल न्यायाधीश के समक्ष एक ज्ञापन दायर किया। हालाँकि, विद्वान सिविल न्यायाधीश ने मूल मुकदमा सं. 17/1995 और निर्देश दिया कि जमा रिकॉर्ड की प्राप्ति के बाद ही किया जा सकता है।

6. प्रमाणित प्रतियों को देखने पर, अपीलार्थी ने देखा कि वास्तविक समय दो सप्ताह का था न कि दो महीने का। इसलिए उन्होंने समय बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया। निम्नलिखित आदेश द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया हैः

"कार्यालय नोट

समय विस्तार के लिए आई. ए. II

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने एस. जे. के समक्ष बी आदेशों के लिए आई. ए. पोस्ट आई. ए. II में बताए गए कारणों के लिए लिखित विवरण दाखिल करने और लागत के भुगतान के लिए निर्धारित समय को 2 महीने तक बढ़ाने का अनुरोध करते हुए एक आई. ए. और हलफनामा दायर किया है।

अदालत के आदेश

सुना गया। आई. ए. 2 को खारिज कर दिया जाता है।"

7. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सदभावी गलती के कारण उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया जा सका और यह तथ्य कि लिखित बयान दिया गया था और दो महीने के भीतर दी गई लागत प्रामाणिक रूप से साबित होती है। उच्च न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए आवेदन को खारिज कर दिया है।

8. नोटिस की तामील के बावजूद उत्तरदाताओं की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है।

9. हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने पर्याप्त आधार का संकेत दिया था कि उच्च न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। आवेदन में सद्भावना को विस्तार से बताया गया है और वास्तव में, वादी द्वारा किए

गए बयानों से इनकार करने वाला कोई जवाब नहीं था क्योंकि विरोधी पक्ष नहीं था।

10. ऐसा होने पर, उच्च न्यायालय ने आवेदन को संक्षेप में अस्वीकार करना उचित नहीं माना। इसलिए, हम उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हैं। लिखित बयान आज से चार सप्ताह के भीतर दायर किया जाए, यदि पहले से ही निचली अदालत के रिकॉर्ड में दायर नहीं किया गया है।- लागत का भुगतान उपरोक्त समय के भीतर किया जाएगा। यदि उपरोक्त शर्तों को पूरा किया जाता है तो 1997 के एम. एफ. ए. संख्या 2323 में दिनांकित 25.6.1999 आदेश को चालू माना जाएगा।

11. अपील की अनुमति लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के दी जाती है।

के. टी. टी.

अपील को अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

**<u>अस्वीकरण</u>** - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।